E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2020; 2(2): 155-157
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 21-05-2020
Accepted: 29-06-2020

राम बाबू चौपाल
गवेषक, राजनीति विज्ञान विभाग,
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
राम बाबू चौपाल
गवेषक, राजनीति विज्ञान विभाग,
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

मिथिला राज्य आन्दोलनः एक राजनीतिक विश्लेषण

राम बाबू चौपाल

सार
पृथक् राज्य के लिए सिर्फ भाषा व संस्कृति ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी देखा जाता है। मिथिला राज्य की मांग सभी दृष्टिकोण से वाजिब है। चाहे मैथिली भाषा बोले जाने वालों की संख्या हो या मिथिलांचल की संस्कृति दोनों ही काफी संपन्न हैं। आर्थिक आधार से देखा जाये तो मिथिलांचल अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा समृद्ध नहीं है। इसलिए पृथक् मिथिला राज्य के गठन की आवश्यकता है। प्रस्तुत पत्र के माध्यम से मिथिला राज्य आन्दोलन पर विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दः मिथिला राज्य, संस्कृति, भाषायी आधार, सुगौली ट्रीटी, राजनीतिक विचारधारा, इतिहास, वर्तमान, आवश्यकता।

प्रस्तावना
मिथिला राज्य की मांग बहुत पुरानी है, बोले तो आजादी से भी पहले की। 1912 में जब बिहार बंगाल प्रोविंस से निकल कर एक अलग स्टेट बना, उसी समय से एक अलग मिथिला स्टेट की मांग शुरू हो गई थी, तब से लेकर अब तक बिहार राज्य से निकलकर 1936 में ओडिशा और 2000 में झारखंड अलग राज्य बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अलग मिथिला राज्य की मांग चलती रही, मिथिला राज्य के एक्टिविस्ट दो मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते रहे। पहली मांग थी, 'मिथिलांचल' के नाम से एक अलग मिथिला राज्य बनाना. और दूसरी मांग मैथिली भाषा को भारत सरकार की आठवीं अनुसूची में शामिल करना। झारखंड के अलग राज्य बनाने के बाद से ये मांगें और भी तेज हो गईं।
ताराकांत झा और दूसरे मैथिल एक्टिविस्ट ने इन मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिए। अटल बिहारी वाजपयी की सरकार ने 2002 में मैथिली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया। तब से इन एक्टिविस्ट का सिंगल पॉइंट एजेंडा है एक नए 'मिथिलांचल' राज्य को बनाना. खास कर तेलंगाना राज्य बनने के बाद से मिथिला क्षेत्र में ऐसे संगठन विस्फोटक तरीके से बनने लगे हैं, पर इस बार युवा लड़के और लड़कियों ने मोर्चा खोला है।
इन्हीं यूथ में से मिथिला मुक्ति मोर्चा की सेक्रेटरी द्वारा बताया गया "पहली बात तो हम बिहारी नहीं हैं, हम मैथिल हैं और यही हमारी पहचान है। हमारे मिथिला को जबरदस्ती बिहार में मिला दिया गया है. और बिहार में हमारे साथ भेदभाव किया जाता है. यहां तक कि बिहार गीत में भी मैथिली और मिथिला की उपेक्षा की गई है। पूरे बिहार गीत में ना तो कवि विद्यापती है ना हीं मां जानकी का उल्लेख है, विकास के नाम पर भी मिथिला की उपेक्षा की गई। आज कोई भी कारखाना, यूनिवर्सिटी खोलने की मांग होती है तो उसे मगध एरिया में धकेल दिया जाता है. आईआईटी की बात हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, मिथिला हमेशा से उपेक्षित रहा है. और यही वजह है जो अलग मिथिला राज्य के आंदोलन को बढ़ावा दे रही है"।[1]
भारत में राज्य भाषा के मुताबिक बने हैं. मिथिला की अपनी एक अलग संस्कृति और एक अलग भाषा है. मिथिला हमेशा से एक अलग राज्य रहा है. यही वो भूमि है जिसने पूरे विश्व को वैशाली के जरिए डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया। हम चाहते हैं कि मिथिला एक अलग स्टेट बने, जिससे उसका विकास हो. सभी धर्म, सभी जाति और सभी जिले के लोग एक साथ आ चुके हैं। बाढ़ मिथिला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आजादी से पहले ही 'लोर्ड वेवेल' ने इसके लिए खास प्रोजेक्ट तैयार किया था। कोसी के बाराह इलाके में हाई डैम बनाना था, इससे मिथिलांचल बाढ़ की तबाही से बचता। लेकिन आजादी के बाद बिहार सरकार ने बहाने बनाकर इस प्रोजेक्ट को ठंढे बस्ते में डाल दिया। अगर इन प्रोजेक्ट्स पर ढंग से काम हो और कोसी नदी पर हाइड्रो पॉवर प्लांट्स लगाएं जाएं तो इससे इतनी एनर्जी जेनरेट होगी कि बिहार और मिथिला ही नहीं पूरे भारत को जगमगाया जा सकता है।

पूर्व क्रिकेटर और दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद भी मिथिला राज्य के आंदोलन में काफी एक्टिव रहे हैं। संसद में उन्होंने मिथिला राज्य के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल इंटरोड्यूस कराया था। मिथिला राज्य के मुद्दे पर कीर्ति आजाद का कहना है, "हम 15वीं लोकसभा में मिथिला राज्य के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आ चुके हैं और साथ ही 377 के अंतर्गत जब संविधान सभा बनी थी, और संविधान पर चर्चा हो रही थी, उस समय में यह तय हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्य बनेगा। जैसे ओड़िया बोलने वालों के लिए ओडिशा, कन्नड़ बोलने वालों के लिए कर्नाटक, मलयालम बोलने वालों के लिए केरल, मराठी बोलने वालों के लए महाराष्ट्र, ऐसे ही और राज्य भी बने. पर मैथिली भाषा तो पूरे भारत में सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, ऐसे में मिथिला राज्य तो बनाना ही चाहिए"।[2]

मैथिली बोलने वाले इलाकों में अलग राज्य के समर्थक सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक जनमत बनाने में जुटे हैं, पर एक सच्चाई ये भी है कि बिहार में ही मगही और भोजपुरी बोलने वाले लोग अलग मिथिला राज्य का विरोध करते हैं। उनका कहना है बिहार से पहले ही दो राज्य ओडिशा और झारखंड निकल चुके हैं. ऐसे में मिथिला राज्य बनाने से बिहार काफी कमजोर हो जाएगा और इसका राजनीतिक महत्व भी कम हो जाएगा.

अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कभी नए राज्य को बनाने की बात होती है तो लोग वैचारिक रूप से दो खेमों में बंट जाते हैं। एक खेमा नए राज्य बनाने के समर्थन में होता है. और दूसरा खेमा उसके विरोध में. समर्थन वाले खेमे का कहना होता है कि नए और छोटे राज्य बनने से गवर्नेंस करने में सुविधा होती है। योजनाओं को लागू कराने में भी दिक्कत नहीं आती. और ऐसे में विकास का काम भी तेजी से हो जाता है. उनकी एक दलील यह भी होती है कि जब अमेरिका जैसा देश, जिसकी आबादी हमसे चार गुना कम है। वहां अगर पचास राज्य हो सकते हैं तो बड़ी आबादी वाले भारत में क्यों नहीं. वहीं नए और छोटे राज्य के विरोधी कहते रहे हैं कि राज्य जितना छोटा होगा लोगों की सोच भी उतनी ही छोटी होती जाएगी। इस सब के बावजूद भी नए और छोटे राज्यों की मांग होती रहती है और नए छोटे राज्य बनाए जाते रहें हैं।

मिथिला क्षेत्र मूल रूप से दो देशों में फैला हुआ है. एक हिस्सा भारत के बिहार में है और दूसरा नेपाल में है। नेपाल को मिथिला का यह इलाका 1816 में हासिल हुआ था। 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच सुगौली ट्रीटी हुई थी. इस ट्रीटी में मिथिला का नॉरर्दन एरिया (जनकपुर, धनुषा, विराटनगर, वीरगंज जैसे जिले) नेपाल को दे दिया गया. और नेपाल से गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम, दार्जलिंग जैसे इलाके ब्रिटिश इंडिया में मिला लिए गए। 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना, तब मैथिली बोलने वाला एक जिला देवघर झारखंड में चला गया। बिहार में इस समय 24 मैथिली बोलने वाले जिले हैं। अलग 'मिथिलांचल' राज्य मांगने का आधार भाषा है।. जिन जिलों में मैथिली बोली जाती है उन जिलों को लेकर राज्य बनाने की बात हो रही है। मैथिली भाषा की कुल चार बोलियां हैं, ये चारों बोलियां हैं वैदेही, वज्जिका, अंगिका और सूर्यपुरी। मिथिला राज्य की मांग तो जोर–शोर से हो रही है. यह एक अलग राज्य बनता है कि नहीं बनता है यह सरकार को तय करना है. लेकिन इसके नाम पर एक आंदोलन तो जरूर खड़ा किया जा रहा है।

इतिहास और वर्तमान

विष्णु पुराण के मिथिला पुराण अध्याय और चंदा झा लिखित रामायण के आधार पर अलग मिथिला राज्य आंदोलन का आधार बताया जा रहा है। लेकिन जार्ज ग्रीर्यसन के 1891 में हुए भारतीय भाषा सर्वेक्षण ने इस बात को और बल देने का काम किया। बिहार के 24 जिलें (अररिया, बांका, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुज्जफरपुर, पुर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली और पश्चिमी चम्पारण) और झारखंड के ६ जिले (देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़) को मिलाकर अलग मिथिला राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है।[3]

झारखंड राज्य के अलग होने के अगले ही दिन यानी 4 अगस्त 2004 को एक प्रेस कांफ्रेस में बिहार के पूर्व महाधिवक्ता एवं भाजपा नेता पं० ताराकांत झा ने अलग मिथिला राज्य हेतु आंदोलन की घोषणा कर दी। भाजपा से निष्कासित होने पर वे मिथिला आंदोलन को समय समय पर हवा देते रहे परन्तु विधान परिषद सदस्य बनते ही उन्होने इस आंदोलन को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

वर्तमान में मिथिला राज्य आंदोलन के लिए सबसे सक्रिय और पुरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद है जिसकी कमान मुख्य रूप से डॉ0 धनाकर ठाकुर और डॉ0 कमल नाथ ठाकुर के हाथों में है, वहीं महासचिव के. एन. झा दिल्ली में रहकर भी कार्यकर्ताओं के संग जमीनी रूप से जुड़े हुए हैं।

उधर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष और विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू भी समय – समय पर मिथिला आंदोलन को हवा देते रहते है। इन्होनें मिथिला आंदोलन को धरना, रैली और बैठकों से आगे बढ़ाते हुए साहित्य अकादमी, मिथिला के नाम पर पुरस्कार और अनुदान को बढ़ावा दिलाने का भी काम किया है, वैसे इनकी सक्रियता मिथिला के बाहर ज्यादा रहती हैं और पूरे देश के मैथिलों को जोड़ने का भी काम इन्होनें किया है।

इसके बाद मिथिला आंदोलन के लिए आगे आए स्व. जयकांत मिश्र और इन्होने मिथिला राज्य संर्घष समिति का गठन किया और मिथिला राज्य आंदोलन को एक नयी आवाज दी। वर्तमान में चुनचुन मिश्र इसके अध्यक्ष एवं उदयशंकर मिश्र इस संस्था के महासचिव हैं।दिल्ली में प्रवासी मैथिलों को जोड़ने के लिए अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेन्द्र प्रसाद यादव एवं महासचिव विजय चंद्र झा की सक्रियता भी दिल्ली में मिथिला आंदोलन को जगाए हुए है।

वहीं यूथ ऑफ मिथिला (अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद की दिल्ली इकाई) और वॉईस ऑफ मिथिला के भवेश नंदन और आनंद कुमार झा जमीनी कार्यकर्त्ताओं, युवाओं एवं बुद्धिजीवियों को जोड़ने में जुटे हैं। यह दोनो संस्था समय – समय पर दिल्ली में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर दिल्ली में अपनी उपस्थिति और मिथिला आंदोलन को हवा देने का काम कर रही है। उसके बाद समय – समय पर मिथिला राज्य के निर्माण के लिए बहुतो लोग आगे आए कभी मिथिलांचल विकास सेना के नाम पर तो कभी दीना भद्री संस्थान, और मिथिला फ़ॉउडेशन आदि के नाम पर लेकिन हाल में दिल्ली के जंतर–मंतर पर चार दिनों का आमरण अनशन कर राजीव कुमार झा उर्फ कवि एकांत ने इस आंदोलन को एक नयी जान देने का काम किया। उन्होनें सभी संगठनों से एकजुट और एकसाथ मिलकर आंदोलन को बढ़ावा देने का न्योता दिया ताकी आंदोलन को मजबूत तरीके से पेश किया जा सके और सरकार पर दबाव बनाया जा सके। अभी राजीव जी राइज फॉर मिथिला के नाम से एक नया दल बनाकर आंदोलन को हवा देने में लगे हैं।

अभी हाल में मिथिला राज्य की लड़ाई के लिए जो संस्था सबसे आगे है वो है मिथिला राज्य निर्माण सेना बहुत कम से सबसे ज्यादा जमीनी कार्य, धरणा प्रदर्शन और चक्का जाम कर देश को प्रमुख लोगों का ध्यान अपने और आकर्षित करने का काम किया। इनके ही प्रयासों के फलस्वरूप भाजपा के सांसद कीर्ति आजाद भी मिथिला राज्य आंदोलन के लिए कूद पड़े हैं। चाहे बात रथ

यात्रा की हो या जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इन्होंने देश के दिग्गज नेताओं को साथ कर आंदोलन का रूख अपनी और करने का काम किया है।

मिथिला आंदोलन की आवश्यकता

तेलांगाना के अलग राज्य की मांग ने मिथिला राज्य आंदोलन को और हवा दे दी है। इस बीच केन्द्र सरकार को दस नये राज्यों के गठन के प्रस्ताव का आवेदन मिलने पर सरकार ने मिथिलांचल राज्य की मांग पर विचार करने की बात कह कर आंदोलनकारियों को लड़ाई लड़ने का एक रास्ता व मुद्दा बना दिया। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय ने अब तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है लेकिन बताया जाता है कि नये राज्य के गठन के संबंध में विभिन्न पक्षों और स्थितियों का अध्ययन कराने के पश्चात ही केन्द्र सरकार कोई निर्णय देगी, जिसका इंतजार इलाके के लोगों को है।

अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना व्याकरण, अपनी लिपी और जनसंख्या के लिहाज से मिथिला एक अलग राज्य होना भी चाहिए। बिहार से बाहर, बिहार का मतलब भोजपुरी होता है। जबकि मैथिली बिहार में प्रमुखता से बोली जाने वाली भाषा है। मीडिया ने भी बिहार का महिमामंडन भोजपुरी से ही किया है। इन्हे बिहार के नाम पर गौतम बुद्ध तो दिखाई देतें है लेकिन जनक और माता सीता नहीं दिखायी देतें। यहाँ तक की बिहार गीत में भी मैथिली और मिथिला की उपेक्षा कि गई पूरे बिहार गीत में ना तो कवी विद्यापति है ना हीं माता जानकी हैं। यहाँ तक की विकास के नाम पर भी मिथिला की उपेक्षा की गई। आज कोई भी कारखाना, विश्वविद्यालय आदि खोलने की मांग होती है तो उसे मगघ क्षेत्र में धकेल दिया जाता है। आई आई टी की बात हो या केन्द्रीय विद्यालय की मिथिला हमेशा से उपेक्षित रही है और यही कारण है जो अलग मिथिला राज्य के आंदोलन को बढ़ावा दे रही है।[4]

बिहार सरकार के उपेक्षाओं का हाल ये है कि आजादी के समय बिहार के राजस्व का कुल 49 फीसदी मिथिला क्षेत्र से आता था और जब 2000 में झारखंड राज्य का बटवारा हुआ तो यह योगदान घटकर मात्र 12 फीसदी रह गई है। यानी मिथिला इन पसास सालों में करीब चार गुणा गरीब हो गई है। यह सोचने वाली बात है जबकि अन्य क्षेत्र अमीर पर अमीर होते जा रहें है मिथिला क्यों पिछड़ता जा रहा है। क्या इस क्षेत्र का पैसा इसी क्षेत्र में लगाया जाता है। अगर नहीं तो ऐसा क्यों। ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अलग मिथिला राज्य के बिना ये संभव नहीं है।

इस तरह बाढ़ भी मिथिला इलाके की प्रमुख समस्या है। लेकिन आजादी से पहले ही लोर्ड वेवेल ने इसके निदान के लिए एक महत्वकांक्षी परियोजना बनाई थी। बाराह क्षेत्र में कोसी पर हाई डैम बनाना था। अनुमान था कि इस परियोजना के पूरा होने से मिथिला क्षेत्र में समृद्धि आएगी और बिहार इस भारी विभीषिका से बच पायेगा। लेकिन आजादी के बाद बनी बिहार सरकार ने बहाने बनाकर इस परियोजना से अपना हाथ खीच लिया और नतीजा हम सबके सामने है। शायद सरकार को डर था कि बाढ़ के नाम पर जो ये लाखों वोट हमें मिथिला क्षेत्र से आता है वह इसके समृद्ध होने के साथ ही समाप्त ना हो जाए। यह बिहार सरकार की अनिच्छा का ही परिणाम था कि केन्द्र सरकार भाखड़ा नंगल परियोजना की और उन्मुख हुई और आज पंजाब का काया–कल्प कर गई। आज पंजाब देश में सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है और उसी पंजाब के खेत में मिथिला के किसान मजदूर बन कर काम करने को मजबूर हो गए है। इधर कोशी बांध परियोजना का पैसा दामोदर घाटी परियोजना में लगाकर मिथिला के साथ एकबार फिर भेदभाव कर दिया गया।

निष्कर्ष

दिल्ली हो या मुंबई, मिथिलावासी हाथ फैलाने को मजबूर है। आज इन मिथिला वासी के ही बदौलत दिल्ली, पंजाब, मुंबई और गुजरात विकास के नित नये आयाम रच रहा है और मिथिला दर – दर की ठोकरें खा रहा है। इसलिए भी ये जरूरी है कि मिथिला राज्य अलग हो क्योंकि जो सपना मिथिला वासी सोते जागते देखते आ रहें है वो बिना मिथिला राज्य के संभव नहीं है।

संदर्भ

1. ठाकुर, उपेन्द्र, 1992, मिथिलाक इतिहास, मैथिली अकादमी, पटना, द्वितीय संस्करण, पृ. 2
2. शर्मा, रामप्रकाश, 2016, मिथिला का इतिहास, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, तृतीय संस्करण पृ. 9
3. ठाकुर, उपेन्द्र, 1988, हिस्ट्री ऑफ मिथिला, मिथिला इंस्टीच्यूट ऑफ पी. जी. स्टडीज एण्ड रिसर्च, दरभंगा, द्वितीय संस्करण, पृ. 4
4. झा, पंकज कुमार, 2010, सुशासन के आईने में नया बिहार, प्रभात प्रकाशन, पटना, पृ. 39